eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 11, November 2025

डिजिटल स्किल तथा रोजगार सृजन: विकसित भारत/2047 के दृष्टिकोण से एक व्याख्यात्मक अध्ययन

श्रीमती माधुरी पाल[1]
[1]असिस्टेंट प्रोफेसर, गृह–विज्ञान, कु0 मायावती राज0 महिला0 स्ना0 महा. बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर (उ.प्र.)

Received: 25 November 2025 Accepted & Reviewed: 28 November 2025, Published: 30 November 2025

Abstract

वर्तमान समय में भारत तेजी से विकसित हो रहा है और डिजिटल युग में डिजिटल कौशल को विकसित कर रहा है। डिजिटल कौशल न केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम है बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक समृद्धि का भी प्रमुख आधार बनता जा रहा है। भारत ने "विकसित भारत @2047" का जो संकल्प लिया है उसको साकार करने के लिए विभिन्न तकनीकी द्वारा संचालित मॉडल की आवश्यकता है। इस शोधपत्र का उद्देश्य डिजिटल स्किल्स,रोजगार कौशल,उद्यमिता,नवाचार,अन्वेषण, भारत के सामाजिक तथा आर्थिक विकास पर इनके प्रभावों का विश्लेषण करना है। इस अध्ययन में डिजिटल शिक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, विभिन्न प्रकार के कौशल विकास कार्यक्रम,कृत्रिम बुद्धिमत्ता,साइबर सुरक्षा,इकोसिस्टम,गिग अर्थव्यवस्था इत्यादि उभरते हुए क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन व मूल्यांकन किया गया है ।

कीवर्ड – डिजिटलाइजेशन, डिजिटल कौशल, तकनीक, रोजगार, विकसित भारत, ऑनलाइन ।

Introduction

संपूर्ण विश्व में भारत देश में सबसे अधिक युवा आबादी निवास करती है,जहां 2024 में औसत आयु लगभग 28 वर्ष रही। यह जनसांख्यकीय लाभ तभी सार्थक सिद्ध होगा, जब देश की युवा पीढ़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था की जरूरत के अनुसार डिजिटल कौशल की जानकारी से संपन्न होगी। डिजिटाइजेशन ने परम्परागत कार्य प्रणालियों,तौर–तरीकों एवं व्यवस्थाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। डिजिटलीकरण ने कार्यस्थल अब भौगोलिक एवं भौतिक अनिवार्यताओं से छूट प्रदान की है और सम्पूर्ण विश्वस्तर के डिजिटल बाजारों में विभिन्न प्रकार के अवसरों की संभावनाएं प्रदान की हैं। वर्ष 2020 के बाद कोविड–19 महामारी ने पूरे विश्व में विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के साथ–साथ डिजिटल परिवर्तन को भी एक नई दिशा दी है । काफी तेज गति से हो रहे डिजिटाइजेशन ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था, संचार व्यवस्था, विभिन्न प्रकार के औद्योगिक इकाइयों इत्यादि के क्षेत्र में काफी क्रांतिकारी रूप से परिवर्तन किया है तथा अपनी सकारात्मकता भी स्थापित की है। डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी कई योजनाएं इस प्रकार के परिवर्तन को सकारात्मक गति प्रदान कर रही हैं। "विकसित भारत @2047" से तात्पर्य है एक ऐसा भारत देश जो आर्थिक रूप से सशक्त एवं उन्नत, तकनीकी रूप से उन्नत, सामाजिक समानता से परिपूर्ण, ज्ञान एवं नवाचार से परिपूर्ण तथा विश्व स्तर पर नेतृत्व क्षमता रखने वाला पूर्ण रूपेण संपन्न एवं समृद्धिशाली हो ।

डिजिटल कौशल– डिजिटल कौशल का तात्पर्य है ऐसी क्षमताएं,व्यावहारिक दक्षताएं, ज्ञान एवं नवाचार इत्यादि को जब मानव विभिन्न प्रकार के डिजिटल उपकरण,अलग–अलग प्लेटफार्म,आधुनिक सॉफ्टवेयर,उन्नत सूचना प्रणालियों और विभिन्न नेटवर्क तकनीकियों का प्रभावशाली उपयोग करने में समर्थ होता है। डिजिटल कौशल की सहायता से मानव इंटरनेट, स्मार्टफोन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, टैबलेट इत्यादि को सुरक्षित तरीके से उपयोग कर सकता है। वर्तमान समय में मानव जीवन में शिक्षा, रोजगार, व्यापार, स्वास्थ्य, शासन या संचार व्यवस्था इत्यादि में डिजिटल क्रांति का समावेश पूर्णता दृष्टिगत होता है। ऐसे में डिजिटल कौशल की योग्यता अनिवार्य प्रतीत होने लगी है । डिजिटल कौशल से तात्पर्य मोबाइल या कंप्यूटर चलाने से नहीं है बल्कि इंटरनेट, डिजिटल टूल्स, साइबर सुरक्षा, क्लाउड तकनीकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल मार्केटिंग, डिजिटल

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 11, November 2025

मार्केटिंग,डाटा सुरक्षा, कोडिंग, डिजिटल जानकारी का विश्लेषण इत्यादि की प्रभावशाली जानकारी एवं उपयोगिता से है। डिजिटल कौशल आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अधिक आवश्यक हो चुका है। तकनीकी अन्वेषण,ऑटोमेशन और डिजिटल शिक्षा के प्रसार,वैश्विक प्रतिद्वंदता ने डिजिटल कौशल का महत्व काफी अधिक बढ़ा दिया है। वर्तमान समय में प्रत्येक नागरिक के लिए डिजिटल कौशल अनिवार्य प्रतीत होने लगा है।

WORLD ECONOMIC FORUM (WEF2020)- के अनुसार "डिजिटल कौशल उन ज्ञान एवं दक्षताओं का समूह है जो कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में कार्य करने अनुसंधान करने और रोजगार प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है।"

Organisation For Economic Co-operation and Development (OECD)– "डिजिटल कौशल में बुनियादी तकनीकी क्षमता से लेकर उन्नत तकनीकी क्षमताएं व दक्षताएं सम्मिलित हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति डिजिटल वातावरण में प्रभावी रूप से संवाद, सहयोग, विश्लेषण और समस्या का समाधान कर सकता है।"

राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन(NDLM भारत सरकार)के अनुसार–"डिजिटल कौशल वह बुनियादी क्षमता है जिसके तहत व्यक्ति डिजिटल उपकरणों जैसे कंप्यूटर, टेबलेट, मोबाइल, इंटरनेट आदि का उपयोग करके दैनिक कार्यों जैसे– दस्तावेज बनाना, ऑनलाइन गतिविधियों, भुगतान, संचार इत्यादि को स्वतंत्र रूप से कर सके।"

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC And CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO 2020)-- "डिजिटल कौशल वह क्षमता है जिसके माध्यम से व्यक्ति डिजिटल उपकरणों संचार अनुप्रयोगों और नेटवर्क का उपयोग करके जानकारी का अभिग्रहण, प्रबंधन, एकीकरण, मूल्यांकन और निर्माण करता है तथा उसे सुरक्षित रूप से साझा करता है।"

डिजिटल कौशल के कुछ प्रमुख तत्वों को इस प्रकार समझा जा सकता है ।

1– तकनीकी कौशल– कंप्यूटर का संचालन, इंटरनेट का उपयोग, मोबाइल एप्लीकेसन की जानकारी, डिजिटल भुगतान करना इत्यादि ।
2– सूचना एवं डेटा कौशल– डेटा खोजना, डाटा का विश्लेषण करना, डाटा सुरक्षित रखना, सूचना प्रबंधन करना ।
3– संचार एवं सहयोग कौशल– वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, ई–मेल भेजना, ई–मेल प्राप्त करना, ऑनलाइन टीमवर्क करना, सोशल मीडिया का प्रबंध करना इत्यादि ।
4– रचनात्मकता एवं कंटेंट निर्माण कौशल– ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग करना, ब्लॉगिंग करना, डिजिटल मार्केटिंग करना इत्यादि ।
5– सुरक्षा एवं नैतिकता– पासवर्ड की सुरक्षा, डाटा गोपनीयता, साइबर जागरूकता, जागरूकता, डिजिटल व्यावहारिक नियम इत्यादि ।
6–उन्नत डिजिटल कौशल– सॉफ्टवेयर का विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, ब्लाकचेन इत्यादि।

आज के युग में डिजिटल तकनीकी ने समस्त विश्व को "ग्लोबल विलेज" में परिवर्तित की कर दिया है। व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, सरकारी सेवाएं, बैंकिंग, संचार इत्यादि सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से प्रभावी रूप से संचालित की जा रही है। जिस व्यक्ति के पास वर्तमान समय में डिजिटल कौशल का अभाव होगा वह विभिन्न प्रकार के अवसरों से वंचित रह जाएगा। डिजिटल कौशल की जानकारी न रखने वाला व्यक्ति वर्तमान समय में रोजगार, शिक्षा, आर्थिक उन्नति एवं सामाजिक भागीदारी

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 11, November 2025

से भी स्वयं को पिछड़ा हुआ महसूस करेगा। वर्तमान समय में डिजिटल कौशल एक विकल्प ही नहीं बल्कि जीविका और प्रगति के लिए पर्याय बन चुका है।

डिजिटल कौशल एवं रोजगार–वर्तमान समय में डिजिटल कौशल वैश्विक बाजार एवं रोजगार हेतु सबसे महत्वपूर्ण योग्यता बन चुका है। पूर्व के समय में जिन कार्यों को पूर्ण रूपेण हाथ से मानव द्वारा किया जाता था उनका स्थान वर्तमान समय में मशीनों, सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन सिस्टम ने ले लिया है। विभिन्न क्षेत्रों जैसे– बैंकों में डिजिटल बैंकिंग, शिक्षा के क्षेत्र में ई–लर्निंग प्लेटफॉर्म, कृषि के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के स्मार्ट एप,सेंसर,ड्रोन,कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए क्लाउड आधारित प्रबंधन तकनीकी डिजिटल कौशल को दर्शाते हैं। डिजिटल तकनीकी ने कई नए रोजगारों को भी उत्पन्न किया है जैसे– ए–आई विशेषज्ञ,डेटा विश्लेषक,डिजिटल मार्केटर,साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ,वेब डेवलपर, एप डेवलपर,कंटेंट क्रिएटर,ई–कॉमर्स प्रबंधक,क्लाउड इंजीनियर,यूआइ/यूएक्स डिजाइनर इत्यादि इन सभी नौकरियां के लिए डिजिटल कौशल की जानकारी होना अनिवार्य है। वर्तमान समय में 90: से अधिक स्टार्टअप डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आधारित है इससे यह स्पष्ट होता है कि डिजिटल कौशल नवाचार के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र को विकास की ओर आगे बढ़ा रहा है। शोध कार्य के क्षेत्र में डिजिटल सिमुलेशन, 3D मॉडलिंग और डाटा विजुलाइजेशन, वर्चुअल लैब जैसे कौशल वैज्ञानिक खोजों, चिकित्सा अनुसंधान,अंतरिक्ष अनुसंधान,इंजीनियरिंग नवाचार इत्यादि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गिग इकोनामी डिजिटल फ्रॉम प्लेटफार्म पर आधारित एक नई रोजगार प्रणाली है जैसे–- SWIGGY, ZOMATO, OLA, UBER, FREELANCER, FIVERR,URBAN COMPANY, UPWORK इत्यादि के माध्यम से लाखों युवाओं को रोजगार प्राप्त हो रहा है। गिग कार्यकर्ता डिजिटल माध्यम से ग्राहकों से जुड़ते हैं भुगतान प्राप्त करते हैं और अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं यह पूरी तरह से डिजिटल कौशल आधारित रोजगार है। महामारी के समय के बाद से विश्व स्तर पर वर्क फ्रॉम होम में काफी वृद्धि हुई है। डिजिटल कौशल का ज्ञान एवं जानकारी ने लोगों को घर से ही,छोटे शहरों से ही वैश्विक स्तर की कंपनियों में काम करने के योग्य बना दिया है। डाटा एंट्री,वर्चुअल अस्सिटेंट,कंटेंट राइटिंग,डिजिटल मार्केटिंग इत्यादि के क्षेत्र में लाखों लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं।डिजिटल कौशल के माध्यम से विभिन्न प्लेटफार्म के द्वारा व्यवसाय भी चलाया जा रहा है। युट्यूब,फेसबुक इंस्टाग्राम,मीशो,शोपिफाई अमेजॉन सेलर इत्यादि प्लेटफॉर्म डिजिटल कौशल के माध्यम से डिजिटल उद्यमिता में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं।

डिजिटल कौशल एवं रोजगार सर्जन हेतु सरकारी योजनायें व नीतियाँ–

डिजिटल इंडिया– भारत सरकार ने 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल सशक्त समाज और ज्ञान आधारित व्यवस्था बनाना है। डिजिटल इंडिया ने भारत में प्रशासन शिक्षा व्यवस्था स्वास्थ्य बैंकिंग व्यापार रोजगार भुगतान सेवा और नागरिक भागीदारी के हर आयाम में विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक परिवर्तन किए हैं । यह कार्यक्रम भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा में केंद्रीय भूमिका निभा रहा है । डिजिटल इंडिया एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य तकनीकी के माध्यम से सामान्य नागरिकों को सरकारी सेवा में जोड़ना,डिजिटल संरचना को मजबूत बनाना,डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना और संपूर्ण देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार करना है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के मुख्य तीन उद्देश्य है– डिजिटल अवसंरचना को नागरिकों तक पहुंचाना,सरकार और सेवाओं को डिजिटल बनाना,और नागरिकों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाना । इसके अंतर्गत सभी क्षेत्रों में मोबाइल और इंटरनेट की पहुँच सुनिश्चित करना, सुरक्षित डिजिटल पहचान,क्लाउड स्टोरेज,सार्वजनिक सेवा वितरण प्लेटफार्म तैयार करना,सभी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन और मोबाइल आधारित बनाना,डिजिटल भुगतान, ई–हेल्थ, ई–एजुकेशन,ई–पासपोर्ट,ई–कोर्ट,ई–गवर्नेंस इत्यादि का विस्तार करना,डिजिटल साक्षरता, डिजिटल रोजगार, डिजिटल उद्यमिता, स्टार्टअप को प्रोत्साहन,ऑनलाइन कौशल

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 11, November 2025

प्रशिक्षण इत्यादि को सम्मिलित किया गया है । डिजिटल इंडिया का लक्ष्य–टेक्नोलॉजी सबके लिए, सबका विकास और सबका डिजिटल सशक्तीकरण है। डिजिटल इंडिया के आठ प्रमुख घटक निम्नलिखित है– ब्रॉडबैंड हाईवे, सार्वभौमिक मोबाइल कनेक्टिविटी, सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई गवर्नेंस–(प्रौद्योगिकी द्वारा सुधार), ई–क्रांति,सूचना के लिए इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन, आईआईटी रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, साइबर सिक्योरिटी ।

इसके अंतर्गत भारत नेट परियोजना के तहत ढाई लाख ग्राम पंचायत तक फाइबर ऑप्टिक केबल पहुंचाना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की समान पहुंच होना सम्मिलित है। दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क 4G और 5G सेवाओं का विस्तार ग्रामीण एवं शहरी डिजिटल खाई को कम करना सार्वभौमिक मोबाइल कनेक्टिविटी पर आधारित है,सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम के अंतर्गत कॉमन सर्विस सेंटर, डिजिटल सेवा केंद्र, जन सेवा केंद्र आदि सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराना है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में यह केंद्र बैंकिंग, बीमा, दस्तावेज सत्यापन,आय प्रमाण पत्र,आधार सेवा इत्यादि संबंधित सुविधाएं एवं कार्य आसानी से कर सके । ई–गवर्नेंस का उद्देश्य सरकारी प्रशासन में पारदर्शिता एवं दक्षता लाना है जिसके अंतर्गत ई–ऑफिस, डिजिलॉकर,ऑनलाइन जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र,भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, ई–डिस्ट्रिक्ट,आधार आधारित प्रमापीकरण इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। मोबाइल निर्माण इकाइयों का विस्तार, सेमीकंडक्टर निर्माण मेक इन इंडिया के अंतर्गत लाखों रोजगार पैदा करना सम्मिलित है। आईटी और रोजगार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, बीपीओ केंद्रों की स्थापना करना, ग्रामीण युवाओं को ई–लर्निंग के माध्यम से रोजगार प्राप्त कराना सम्मिलित है। साइबर सिक्योरिटी कार्यक्रम के अंतर्गत डिजिटल भुगतान, सुरक्षा,साइबर अपराध की रोकथाम, डाटा गोपनीयता संबंधी नियम, सूचना सुरक्षा ढांचा, इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। इन सभी तत्वों को आपस में सम्मिलित कर डिजिटल इंडिया को व्यापक कार्यक्रम के रूप में जाना जा सकता है। डिजिटल इंडिया की प्रमुख उपलब्धियां में आधार, डिजिटल भुगतान क्रांति, इंडिया स्टैक, COWIN पोर्टल, डिजिलॉकर, ई–शिक्षा, कॉमन सर्विस सेंटर, रोजगार सृजन इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। डिजिटल इंडियाभारत की अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन ला रहा है। 2025 तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। MSME का डिजिटलकरण होने से छोटे व्यवसायों को भी ऑनलाइन बाजार प्राप्त हो गया है। जीएसटी,UPI, GEM (सरकारी ई–मार्केट प्लेस),ONDC(ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स) ने व्यापार की प्रक्रिया को आसान कर दिया है।

स्टार्टअप इंडिया – स्टार्टअप इंडिया को 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लांच किया गया स्टार्टअप इंडिया सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी पहल है जिसका उद्देश्य भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देना,युवाओं को नवाचार के लिए प्रोत्साहित करना,नए स्टार्टअप्स की स्थापना करना,वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा रोजगार के सर्जन को बढ़ावा देना है । 21वीं सदी के डिजिटलीकृत और नवाचारित परिवेश में स्टार्टअप इंडिया भारत को एक अन्वेषण संचालित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है । यह भारत को विकसित भारत@2047 की ओर तेजी से लेना जाने में सक्षम होगी । भारत सरकार के DPIIT(डिपार्मेंट आफ प्रमोशन आफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड) के अनुसार किसी फर्म को स्टार्टअप माना जाता है यदि–उसकी उम्र 10 वर्ष से कम हो,उसका वार्षिक टर्नओवर 100 करोड रुपए से कम हो, वह कोई नया उत्पाद/ सेवा/ प्रक्रिया नवाचार के आधार पर विकसित कर रहा हो । स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत स्टार्टअप शुरू करने हेतु सेल्फ सर्टिफिकेशन करना आसान हो गया है, 48 घंटे में कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। श्रम कानून में छूट, 3 वर्ष के लिए कर छूट, निवेश पर छूट, 90 दिनों में विंड अप सुविधा भी उपलब्ध है। स्टार्टअप इंडिया दुनिया में अमेरिका तथा चीन के बाद तीसरा बड़ा स्टार्टअप है। भारत में 100 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप जैसे– पेटीएम, BYJU'S, SWIGGY, ZOMATO, OYO, NYKAA इत्यादि यूनिकॉर्न तैयार किए हैं।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 11, November 2025

स्किल इंडिया मिशन– स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को भारत सरकार द्वारा की गई। इस मिशन का उद्देश्य युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें उद्यमिता और उत्पादन शीलता संबंधी गतिविधियों से जोड़ने के लिए तैयार करना है ताकि वह देश की आर्थिक विकास में अपना योगदान दे सके और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सके । स्किल इंडिया मिशन के मुख्य उद्देश्य में देश के युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करना,उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण देना,उद्यमिता कौशल विकसित करना,भारत की महिलाओं ग्रामीण युवाओं दिव्यांगजनों और पिछड़े वर्ग को कौशल प्रशिक्षण से जोड़ना,अनौपचारिक कौशल रखने वाले लोगों को प्रमाणित करना,भारत को वैश्विक स्तरीय कौशल हब बनाना इत्यादि प्रमुख है । प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवाओं को मुक्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । यह देश की सबसे बड़ी कौशल प्रशिक्षण योजना है,प्रशिक्षण पूरा होने के पश्चात स्किल सर्टिफिकेट और रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिलती है । इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग तथा "रिकॉग्निएजेशन आफ प्रीवियस लर्निंग" की व्यवस्था है । राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अंतर्गत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलता है। विभिन्न सेक्टर स्किल काउंसलिंग के माध्यम से उद्योगों संबंधी प्रशिक्षण मानक निर्धारित किए जाते हैं । स्किल इंडिया मिशन को सफल बनाने के लिए उद्योगों की भागीदारी को बढ़ाना सुनिश्चित करना होगा तथा डिजिटल स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था का विस्तार भी करना होगा। स्कूल स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का संचालन तथा प्रशिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण व्यवस्था भी करनी होगी। ग्रामीण तथा दूर दराज के क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (**PMKVY**)– भारत सरकार ने देश में रोजगार की समस्या एवं युवाओं में कौशल विकास की कमी को ध्यान में रखते हुए 15 जुलाई सन 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की। जिसका उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार रोजगार उपयुक्त कौशल प्रदान करना है। यह योजना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संचालित और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा लागू की जाती है। इस योजना के अंतर्गत देश के युवाओं को मुफ्त में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि वे प्रशिक्षण प्राप्त करके उद्योग आधारित कौशल विकास में रोजगार प्राप्त कर सके । यह योजना पिछड़े वर्ग को, महिलाओं और ग्रामीण युवाओं तक कौशल प्रशिक्षण को प्रदान करती है तथा पहले से मौजूद अनौपचारिक कौशल का प्रमाणन भी करती है । प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत उम्मीदवारों को पूरी तरीके से निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । प्रशिक्षण की शुल्क का भुगतान भारत सरकार स्वयं करती है । इस प्रशिक्षण की अवधि 150 से 300 घंटे निर्धारित की गई है प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता को स्किल सर्टिफिकेट रोजगार सहायता एवं जॉब इंटरव्यू की व्यवस्था भी की गई है। प्रशिक्षित युवाओं को जॉब फेयर नौकरी मिल और उद्योग केंद्रित प्लेसमेंट ड्राइव सेल जोड़ा जाता है तथा एनएसडीसी तथा सेक्टर स्किल काउंसिल उद्योगों से संपर्क करके उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत डिजिटल डिजिटल कौशल,ऑटोमोबाइल,हेल्थ केयर,औद्योगिक एवं तकनीकी कौशल,टूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी, ब्यूटी एवं वैलनेस, कृषि संबंधित कौशल, ग्रीन स्किल्स इत्यादि क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आधुनिक भारत के युवाओं को आत्मनिर्भर रोजगार योग्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है यदि इस योजना को और बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया जाए ।

राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन – राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन भारत सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण पहल जिसका उद्देश्य भारत के प्रत्येक नागरिक को डिजिटल तकनीक के उपयोग में सक्षम बनाना है ताकि वे डिजिटल माध्यम से मिलने वाली सेवाओं से ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, ई–गवर्नेंस सेवाओं का लाभ उठा सके । डिजिटल विभाजन को कम करने के उद्देश्य से 2014–15 में NDLM/ DISHA की की शुरुआत की गई, राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 11, November 2025

मिशन का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है। सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बंधित सेवाओं का लाभ सभी तक पहुंचाना तथा सशक्त भारतीय डिजिटल भारत के सपने को पूरा करना है। राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन से करोड़ नागरिक डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या काफी स्तर तक बड़ी है । CSC केन्द्रों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है जिससे ग्रामीणों को पर स्थानीय स्तर पर डिजिटल सुविधा प्राप्त हो रही है डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे पहुंच चुका है।

मेक इन इंडिया ––भारत सरकार ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत की यह देश की औद्योगिक नीति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण एक सुधारात्मक प्रक्रिया है जिससे न केवल घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिला बल्कि अंतरराष्ट्रीय निर्देशकों के लिए भारत को एक अनुकूल व्यवस्था के रूप में स्थापित किया गया भारत की स्थिति को बदलने, भारतीय उद्योगों को सशक्त बनाने एवं युवाओं में बेरोजगारी की संख्या को कम करने के लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की गई। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बनाना है जिससे भारतीय उद्योग विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा स्थापित कर सके और विदेशी कंपनियां भारत में उत्पादन कर सकें। घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर देश की आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं का देश में उत्पादन करके आयात पर निर्भरता को कम करना मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य है जिससे देश के लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। मेक इन इंडिया विदेशी निवेशकों को भारत में व्यापार करने और उद्योग स्थापित करने के लिए भी प्रेरित करता है। मेक इन इंडिया के तहत 25 प्रमुख क्षेत्र हैं जैसे–ऑटोमोबाइल,रक्षा उत्पादन,इलेक्ट्रॉनिक,रसायन,फार्मास्यूटिकल्स,खाद्य प्रसंस्करण,रेलवे,खनन,अंतरिक्ष,नवीकरणीय ऊर्जा, ऑटोमोबाइल कॉम्पोनेंट्स, एयरोस्पेस, बायोटेक्नोलॉजी, सड़क एवं हाईवे, स्वास्थ्य सेवा, वस्त्र एवं परिधान, पर्यटन एवं आतिथ्य, मीडिया और मनोरंजन, थर्मल पावर, इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर, बंदरगाह और जहाज निर्माण, मशीनरी, तेल और गैस ।

इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि डिजिटल कौशल से भारतीय अर्थव्यवस्था विभिन्न रूपों से प्रभावित हुई है। डिजिटल स्किल द्वारा उत्पादन,वितरण, उपभोक्ता की संपूर्ण प्रक्रिया परिवर्तित हुई है। डिजिटल शिक्षा प्राप्त कर कौशल आधारित सीखने के अवसरों में रोजगार योग्यता को बढ़ावा दिया है जिससे स्टार्टअप, तकनीकी समाधान और आर्थिक विकास में सहायता मिली है परंतु डिजिटल डिवाइड और गुणवत्ता संबंधित कठिनाइयाँ अभी भी उपस्थित है। डिजिटल शिक्षा ने भारत को ज्ञान आधारित अन्वेषण में सक्षम और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए डिजिटल कौशलों पर आधारित विकास मॉडल को मजबूती से तैयार करना होगा तथा उनका सही रूप से क्रियान्वयन भी करना होगा ।

REFERENCES-

Ministry of Electronics and Information Technology. (2023). Digital India: Transforming governance and service delivery. Government of India.

NITI Aayog. (2022). India's digital ecosystem: Vision 2047. Government of India.

World Bank. (2021). Digital skills for employment and inclusion. World Bank Publications.

UNESCO. (2020). Digital literacy and workforce development in emerging economies. UNESCO Publishing.

OECD. (2019). Skills for the digital transformation. OECD Publishing.

McKinsey Global Institute. (2021). The future of work in the digital age: Global and Indian perspectives. McKinsey & Company.

FICCI. (2023). Digital skills and employability in India: Trends, challenges, and opportunities. Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry.

Gupta, R., & Sharma, P. (2022). Digital competency and employment creation in India: Opportunities for youth. International Journal of Digital Education, 14(2), 45–58.

Kumar, S. (2021). Digital skill development and future-ready workforce in India. Journal of Skills and Innovation, 9(1), 72–89.

Ministry of Skill Development & Entrepreneurship. (2023). National skill development report. Government of India.

Economic Survey of India. (2022). Digital economy and employment trends. Ministry of Finance, Government of India.